(*Unit area in '000 hectares*)

Crop	1967-68 Coverage prior to the introduction of crash programme	1968-69 Coverage during the first year of crash programme	1969-70 Coverage during the second year of crash programme (Provisional)
HV Kharif Paddy	101	195	486
HV Boro Paddy	25	51	81
HV Wheat	31	82	176

An additional area of 2.32 lakh hectares was covered under multiple cropping programme during the first year of crash programme of 1968-69 as against 1.71 lakh hectares covered in the preceding year. The figures of achievements for 1969-70 are not yet available.

As regards provision of additional irrigation facilities, in 1968-69 about 11,500 shallow tubewells were installed by the State against the target of 20,000 tubewells. The State Government, however, maintained the original target of sinking 20,000 shallow tubewells during 1969-70. According to the information so far received, 1,333 shallow tubewells were sunk upto December, 1969.

The State Government had envisaged a production target of 60 lakh tonnes of cereals for 1968-69 and 70 lakh tonnes of cereals for 1969-70. Production of cereals during 1968-69 exceeded the target. Final estimates of production of cereal crops for 1969-70 are not yet available. The State Government, however, expects that the target is likely to be reached.

बिहार और उत्तर प्रदेश डीजल इंजन पम्पिग सैट और विद्युत् चालित पम्पिग सैट लगाने की नीति

*1188. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में कुल जितने क्षेत्र में खेती की जाती है वह देश की कुल कृषि भूमि का एक चौथाई है और इन राज्यों में 80 प्रतिशत भूमि में पर्याप्त पानी उपलब्ध है ;

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु और महाराष्ट्र में चल रहे 2.25 लाख डीजल-इंजन पम्पिग सैट तथा 5 लाख विद्युत चालित पम्पिग सैटों की तुलना में इन राज्यों में 1969 तक केवल एक लाख डीजल इंजन पम्पिग सैट और 1.25 लाख विद्युत चालित पम्पिग सैट लगाये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस सम्बंध में बिहार तथा उत्तर प्रदेश सरकारों द्वारा अपनाई जा रही नीति का अध्ययन करने और गतिरोध को दूर करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) बिहार तथा उत्तर प्रदेश में जो भूमि कृषिगत है वह देश भर की कृषिगत भूमि का 20 प्रतिशत भाग है। उपलब्ध जल संसाधनों के विस्तृत मूल्यांकन के अनुसार यह अनुमान किया गया है कि बिहार में अन्ततः कुल कृषिगत भूमि के 85.9 प्रतिशत भाग तथा उत्तर प्रदेश में कुल कृषिगत भूमि के 68.5 प्रतिशत भाग में सिंचाई हो सकेगी।

(ख) इन राज्यों में पम्प सैटों के विषय में हुई असमान प्रगति के कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) महाराष्ट्र में सब सिंचाई सुविधाओं

की तुलनात्मक कमी के फलस्वरूप मांग बढ़ गई और पम्प सैटों के लगाने पर बल दिया गया। अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में इस कार्यक्रम की सहायता के लिये संस्थागत वित्त (जो कि पम्प सैटों सहित गैर-सरकारी लघु सिंचाई कार्यों के लिये परिव्यय की बड़ी राशि प्रदान करता है) का काफी पहले विकास किया गया।

(2) तमिलनाडु में सतही जल संसाधनों का विकास अधिकांशतः संतृप्ति स्तर पर पहुंच गया है। अतः खुदाई के कुओं तथा पम्प सैटों के लगाने के लिये सम्मिलित मांग बढ़ गई। पम्प सैटों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये अन्य राज्यों की तुलना में तमिलनाडु सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को काफी पहले शुरू कर दिया था।

(3) बिहार तथा उत्तर प्रदेश में केवल 1966 में अत्यधिक सूखा पड़ने तथा अधिक उत्पादनशील किस्मों की सफल शुरूवात के पश्चात् गैर-सरकारी लघु सिंचाई कार्यों (पम्प सैटों सहित) के कार्यक्रमों और ग्रामीण विद्युतीकरण में काफी प्रगति हुई है।

(ग) लघु सिंचाई (पम्प सैटों सहित) के सम्बन्ध में बिहार तथा उत्तर प्रदेश सरकारों के कार्यक्रमों तथा नीतियों का निरन्तर रूप से पुनरीक्षण किया जा रहा है और बिजली तथा डीजल पम्प सैट लगाने सहित लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिये अत्यधिक प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों पर जोर दिया जा रहा है।

बिना डाकघर वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलते-फिरते डाकघर

*1189. **श्री देवेन सेन :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां डाकघर नहीं हैं अथवा जहां डाकघर बहुत दूरी पर स्थित हैं, चलते-फिरते डाकघरों की सुविधा प्रदान करेगी ;

(ख) यदि हां, तो कब तक ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) सभी सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कोई डाकघर नहीं है या जहां डाकघर दूरदराज स्थानों पर स्थित हैं, वहां फिलहाल चलते-फिरते डाकघरों की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) हमारे देश के विकास की वर्तमान स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सुविधाओं के विस्तार के लिए चलते-फिरते डाकघरों को अपेक्षा स्थिर डाकघरों के जरिये ये सुविधाएं प्रदान करने में कहीं अधिक किफायत होती है। जिन क्षेत्रों में इन सुविधाओं के विस्तार का औचित्य है, वहां मोटर लायक सड़कों की कमी, ऐसे वाहनों के लिए रख-रखाव की समुचित सुविधाओं के अभाव और सुरक्षा की दृष्टि से चलते-फिरते डाकघरों के प्रचालन की गम्भीर कठिनाइयां हैं।

Study of cost of Labour and Production in Selected Industries

*1190. SHRI VIRENDRAKUMAR SHAH: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether there is a general belief that the cost of labour in developing countries like India is lower than in developed countries like the U. S. A.;